मोबाइल क्रांति ने दी ग्रामीण विकास को नई दिशा

—डॉ. नीरज कुमार गौतम

वर्तमान परिपेक्ष्य में मोबाइल के माध्यम से गांव के प्रत्येक क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इंटरनेट और तकनीक का विस्तार प्रस्तावित सभी दिशाओं में तेजी से हुआ है। आधुनिक तकनीक और डाटा प्रबंधन ने सरकार और नागरिकों के बीच के अंतर को पाटा है। इसका सीधा असर नागरिक सहभागिता और जन-जागरुकता पर पड़ता है, जिससे लोकतंत्र सुदृढ़ होता है।

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मोबाइल क्रांति ने आम आदमी के साथ–साथ ग्रामीण परिदृश्य में बहुत अधिक बदलाव ला दिया है। वास्तव में मोबाइल हमारे सामाजिक, आर्थिक जीवन का अहम् हिस्सा बन गया है और इसने हमारे सोचने, काम करने, प्रतिक्रिया व्यक्त करने, बातचीत करने और जीवनशैली में बहुत अधिक परिवर्तन किया है। अब तो मोबाइल के बिना जीवन की कल्पना करना भी कठिन–सा हो गया है।

मनुष्य प्रारम्भ से ही सूचना प्राप्ति एवं उसके प्रेषण के लिए नाना प्रकार से क्रियाशील रहा है क्योंकि हर व्यक्ति के लिए सूचना का अपना महत्व है। संचार व्यैक्तिक या समूह के साथ स्थापित होता है, इसी से जुड़े जनसंचार का संबंध अपनी जन–सम्प्रेषणीयता जनसमूह तक पहुंचाना है। जनसंचार माध्यमों के रूप में आज रेडियो, टी.वी., फिल्म, वीडियो, इंटरनेट, टेलीफोन, प्रेस आदि की भूमिका सर्वोपरि है। इन माध्यमों के द्वारा हम समूह तक शिक्षा, मनोरंजन एवं सूचना प्रेषित करते हैं। आधुनिक समाज के लिये ये माध्यम अनेक रूप में उपयोगी हैं।

आज का युग वैज्ञानिक युग है। एक राष्ट्र के सामाजिक, आर्थिक विकास के लिए दूरसंचार, मोबाइल सेवाओं को विश्व भर में एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में मान्यता दी गई है। भारत गांवों का देश है जिसकी 70 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में निवास करती है, जिसका मुख्य व्यवसाय कृषि है। कृषि प्रधान देश होने के कारण आज गांव से शहरों का सीधा सम्पर्क न होना विकास में बाधक बन रहा है किन्तु मोबाइल क्रांति ने सारे विश्व को एक साथ जोड़ दिया है। आज प्रत्येक योजना, जानकारी, घटना, शासकीय नीतियां, सूचना सीधे मोबाइल के माध्यम से प्रत्येक गांव में प्रत्येक व्यक्ति से जुड़ी हुई हैं।

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में शासकीय व अशासकीय प्रत्येक कार्य को सीधा मोबाइल के माध्यम से जोड़ा गया है। चाहे वह ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा हुआ क्यों न हो। आज मोबाइल के माध्यम से इंटरनेट, कम्प्यूटर, बैंक की कार्यप्रणाली, किसानों से जुड़ी योजनाएं, मेल, एस.एम.एस. आदि प्रत्येक कार्य मोबाइल के माध्यम से ही किए जा रहे हैं। प्रारम्भ में दूरसंचार सेवाओं का उपयोग मुख्यतः सरकारी, व्यापारिक एवं उद्योग क्षेत्र में किया जाता था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद दूरसंचार के क्षेत्र में तेजी आई और दूरसंचार उपकरणों का निर्माण सार्वजनिक क्षेत्र में किया जाने लगा और इसके बाद दूरसंचार सेवाओं का विस्तार सरकारी कार्यालय, व्यापारिक एवं औद्योगिक प्रतिष्ठान और कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में हो गया। इस समय ग्रामीण क्षेत्रों में खेती संबंधी जानकारी, मौसम की जानकारी, मण्डी के भाव

आदि जानने के लिए दूरसंचार सेवाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब तो हर घर में दूरदर्शन एवं मोबाइल फोन की सुविधा उपलब्ध है और प्रत्येक पंचायत को दूरसंचार सेवाओं से लैस करने के प्रयास किए जा रहे हैं। देश के हर गांव को दूरसंचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी से जोड़ने की दिशा में लगातार कामयाबी मिल रही है। इसका असर गांवों में स्पष्ट रूप से दिख भी रहा है। संचार सुविधाओं के गांव–स्तर पर पहुंचने के साथ ही रोजगार भी बढ़े हैं।

केन्द्र सरकार की ओर से भारत निर्माण के तहत् ग्रामीण दूरसंचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने की लगातार कोशिशें चल रही हैं। भारत निर्माण के तहत् संचार और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में किए गए प्रयासों का असर है कि आज हर व्यक्ति के पास संचार सुविधा उपलब्ध हो गई है। कुछ परिवारों में तो हर व्यक्ति के पास मोबाइल उपलब्ध हैं। वहीं ग्रामीण इलाके की दुर्गम पहाड़ियों और रेतीले धोरों के बीच बसे लोगों के घरों में टेलीफोन की घंटियां घनघनाने लगी हैं। हर गांव को ब्रॉडबैंड से जोड़ा जा रहा है। इस योजना को अमलीजामा पहनाने का सबसे बड़ा फायदा यह हो रहा है कि ग्रामीणों को अपने ही गांव में हर तरफ की सुविधाएं मिल पा रही हैं।

दूरसंचार : भूमण्डलीकरण के इस दौर में सूचनाओं का आदान–प्रदान तेजी से हो रहा है। इस बदलाव की तुलना हम वैश्विक गांव से करते हैं। दुनिया एक–दूसरे के नजदीक तेजी से आ रही है। तेजी से बढ़ती ये नजदीकियां सूचनाओं के सम्प्रेषण की तीव्रता से लाभान्वित होकर विकास को प्राप्त कर रही हैं। सूचना क्रांति के इस युग में यह जरूरी हो गया है कि उन वंचित लोगों को इसके दायरे में लाया जाए जो संचार साधनों के अभाव के कारण पिछड़ रहे हैं। सूचनाएं मानव जीवन में निर्देशन और परामर्श का काम करती हैं तथा सर्वांगीण विकास के लिए लक्ष्य और कार्यक्रमों का सृजन करती हैं। एक सही सूचना मानव जीवन को बदलने और विकसित करने की क्षमता रखती है। इस तथ्य को जीवन का आधार मानते हुए भारत निर्माण में दूरसंचार को शामिल किया गया। इस योजना के अंतर्गत 2007 के अंत तक छूटे हुए 66822 गांवों में टेलीफोन सुविधा प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया था, जो सितम्बर 2009 को पूरा कर लिया गया था।

ग्रामीण टेलीफोन : 21वीं शताब्दी के अंत तक पूरी दुनिया संचार क्रांति के दौर में प्रवेश कर गई है। संचार के विभिन्न साधनों के कारण दूरदराज गांव में बैठा हुआ व्यक्ति दुनिया में हर जगह पहुंच गया है। हालांकि ऊपरी तौर पर तो टेलीफोन केवल हालचाल जानने का साधन मालूम पड़ता है, लेकिन किसी भी व्यक्ति और उस क्षेत्र के आर्थिक विकास का यह एक आधारभूत तत्व है। गांवों के लोगों के लिए तो यह इसलिए और भी अधिक जरूरी हो जाता है क्योंकि इसके अभाव में वे मुख्यधारा से अलग ही रह जाते हैं।

इसलिए केन्द्र सरकार ने जहां गांवों को शहरों से जोड़ने के लिए सड़कें बनाने पर जोर दिया है, वहीं गांवों को देशभर से जोड़ने के लिए टेलीफोन उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया है। केन्द्र सरकार की इच्छा है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में दूरसंचार की सुविधाओं में जो काफी अंतर है, उसे कम किया जाए। ग्रामीण टेलीफोन योजना के अंतर्गत केन्द्र सरकार ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में लोगों को सस्ती और उचित दरों पर बुनियादी दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध कराएगी।

गांवों में मोबाइल सम्पर्क क्रांति : देश के दूरसंचार सेवा से वंचित गांवों में चरणबद्ध रूप में मोबाइल संचार सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु समय–समय पर सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) योजनाएं तैयार

ग्रामीण दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी से बढ़ेगा उत्पादन

भारत निर्माण कार्यक्रम के तहत् ग्रामीण दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी का विस्तार होने से देश में विभिन्न स्तरों पर उत्पादन भी बढ़ेगा। ग्रामीण इलाके में सबसे ज्यादा फायदा कृषि उत्पादन को मिलेगा। किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सकेगा और कम लागत में अधिक मुनाफा भी कमा सकेंगे, क्योंकि अभी तक किसानों को अपनी विभिन्न समस्याओं के निस्तारण के लिए कृषि विशेषज्ञों तक पहुंचने में काफी पैसा और समय खर्च करना पड़ता है। सूचना प्रौद्योगिकी का दायरा ग्रामीण स्तर पर होने से वे तुरन्त अपनी समस्या का समाधान कर सकेंगे। अभी तक के अनुभव भी यही बता रहे हैं कि जिस गति से संचार क्रांति आगे बढ़ रही है, उसी गति से कृषि को भी बढ़ावा मिला है। संचार क्रांति से कृषि संबंधित तकनीकी जानकारी किसानों को पहले की अपेक्षा कई गुना बेहतर और समय से मिल रही है। आज भारत का किसान एस.एम.एस. के जरिए मौसम की जानकारी प्राप्त कर रहा है तो किसान कॉल सेंटर और ई–चौपाल जैसी सुविधाओं से खेती में होने वाले खतरे कम हो रहे हैं। ऐसे में खाद्यान्न उत्पादन बढ़ने के साथ ही गुणवत्तापरक खेती के प्रति भी लोगों का झुकाव बढ़ा है। किसान इंटरनेट के जरिए मंडियों के ताजा भाव के बारे में जान सकता है और भण्डारण की तकनीक भी सीख सकता है। संचार क्रांति के इस युग में किसानों को विभिन्न तरह की सूचनाओं से लैस तो किया ही गया, अब किसान ई–खेती की ओर अग्रसर हो रहे हैं।

की जाती हैं। ऐसे ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्र जहां अभी फिक्सड वायरलैस और मोबाइल कवरेज नहीं हैं, वहां मोबाइल सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु 27 राज्यों के पांच सौ जिलों में 7353 अवसंरचना स्थलों/टावरों को संस्थापित करने तथा उनका संचालन करने के लिए यूएसओ निधि द्वारा साझा मोबाइल अवसंरचना योजना शुरू की गई है। ऐसे गांवों या गांवों के समूह जिनकी आबादी दो हजार या इससे अधिक हो और जहां मोबाइल कवरेज उपलब्ध न हो, वहां इस योजना के तहत् टावर स्थापित करने के लिए विचार किया गया था।

संचार क्रांति के इस युग में वैश्विक स्तर पर सामाजिक सम्पर्कों को जोड़ने या अपनी बात को तत्काल दूसरों तक पहुंचाने में सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स का कोई विकल्प नहीं है। ये साइट्स संदेशों के आदान–प्रदान का त्वरित व सुगम माध्यम बन चुकी हैं। यही कारण है कि इनका चलन तेजी से बढ़ रहा है। युवा वर्ग तो इनका दीवाना है। इंटरनेट संवाद और जानकारियों का अथाह भंडार है। सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स ने न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर, बल्कि वैश्विक स्तर पर अभिव्यक्ति को नए आयाम दिए हैं और विश्व गांव की परिकल्पना को साकार किया है। इसी के साथ सामाजिक और बौद्धिक विकास को भी गति दी है। सच तो यह है कि इंटरनेट आज विकसित जीवनशैली वाले वर्ग के जीवन का एक ऐसा हिस्सा बन चुका है, जिसके बिना वह कुछ भी कर पाने में असहज महसूस करता है। अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर सोशल मीडिया के कुछ बहुत ही सकारात्मक परिणाम देखने को मिल चुके हैं। मसलन कुछ समय पहले अरब देशों में जहां सोशल मीडिया ने युवकों को एकजुट करते हुए तानाशाही के खिलाफ क्रांति को संभव बनाया, वहीं भारत में भ्रष्टाचार के खिलाफ छेड़े गए राष्ट्रव्यापी अभियान को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

ग्रामीण मोबाइल उपभोक्ताओं की संख्या 35 करोड़ के पार : देश के ग्रामीण इलाकों में मोबाइल एवं इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या 35 करोड़ के पार पहुंच गई है। सेल्यूलर मोबाइल ऑपरेटरों के संगठन (सीओएआई) के अनुसार ग्रामीण इलाकों में ग्राहकों की संख्या 36.9 लाख बढ़कर 35 करोड़ 1 लाख पर पहुंच गई। आंकड़ों के अनुसार सबसे ज्यादा 3.71 करोड़ से अधिक ग्रामीण मोबाइल एवं इंटरनेट उपभोक्ता बिहार, झारखण्ड सर्कल में हैं। ग्रामीण उपभोक्ताओं की संख्या में सर्वाधिक 18.1 लाख की बढ़ोतरी सर्कल बी के इलाकों में दर्ज की गई।

मोबाइल की पहुंच : आज विश्व में पांच अरब मोबाइल कनेक्शन हैं, लेकिन कुछ विकसित देशों में जितनी जनसंख्या है उससे दुगुनी संख्या में मोबाइल हैं। वर्ष 2015 तक भी विश्व की केवल 50 प्रतिशत जनसंख्या के पास ही मोबाइल था और इसे सौ प्रतिशत होने में 2020 तक का समय लगेगा। एक रिपोर्ट के अनुसार इस समय मोबाइल फोन के सिग्नल पृथ्वी के 90 प्रतिशत हिस्सों पर पहुंच रहे हैं। इस तरह पूरे विश्व में कहीं भी कोई भी व्यक्ति मोबाइल फोन का उपयोग कर सकेगा। दुनिया के ग्रामीण इलाकों में 75 प्रतिशत जनसंख्या तक मोबाइल सिग्नल पहुंचता है और ग्रामीण इलाकों की 50 प्रतिशत जनता इसका उपयोग करती है। इस रिपोर्ट में एक अहम सिफारिश की गई कि सभी देशों को 2015 तक दुनिया की आधी आबादी तक ब्रॉडबैंड नेटवर्क ले जाने के लिए तेज गति से कदम उठाने चाहिए, क्योंकि ब्रॉडबैंड मोबाइल से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ब्रॉडबैंड के जरिए शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण और अन्य क्षेत्रों में जानकारी का आदान–प्रदान हो सकेगा। इसमें ब्रॉडबैंड के जरिए स्कूलों, विश्वविद्यालयों, शोध केन्द्रों और अस्पतालों को परस्पर जोड़ने पर जोर दिया है।

भारत सरकार द्वारा डिजिटल इंडिया के अंतर्गत किए गए कार्यों में से ग्रामीण भारत में किसानों के लाभ के लिए ई–सूचना कार्यक्रमों में उत्तरोतर वृद्धि से सम्पूर्ण भारत विशेषकर गुजरात के किसानों ने बखूबी लाभ उठाया। हाल के वर्षों में कम्प्यूटर आधारित मोबाइल से सूचना प्राप्त करने में ग्रामीण भारत में 35 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई। उपरोक्त संकेत सरकार और किसानों के बीच एक सकारात्मक संवाद और भविष्य में ई–सूचना से भारतीय किसानों को होने वाले लाभ को भी दर्शाते हैं। भारत सरकार ने ग्रामीण भारत के किसानों को एक वेब–आधारित पोर्टल मोबाइल पर उपलब्ध कराया है जोकि भारत भर में फैले 8 करोड़ ग्रामीण परिवारों से सम्पर्क कर मोबाइल संदेशों/वीडियो के जरिए सरकार के विभिन्न संगठनों/कार्यालयों से प्राप्त कर सुन/पढ़/देख बातचीत कर सकते हैं। उपरोक्त वीडियो में बात करता एक भारतीय किसान निरन्तर इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों की बढ़ती

डिजिटल इंडिया - एक कदम गांवों की ओर भी

डिजिटल इंडिया : प्रधानमंत्री का स्वप्न भारत के प्रत्येक नागरिक को इंटरनेट की विशाल दुनिया से जोड़कर ग्लोबल बनाने का है। एक उद्देश्य सबको सशक्त बनाने का और उन 'जुबानों' को भी आवाज देने का है जिनकी बात की पहुंच सीमित थी। अगर प्रधानमंत्री के शब्दों में कहें तो डिजिटल इंडिया एक ऐसी क्रांति है जो बिना किसी सीमा को जाने–पहचाने लोगों को सूचना का अधिकार देती है। मुख्य रूप से गांवों को इंटरनेट प्रदत्त बनाने के लिए प्रकल्पित ये परियोजना, वर्तमान में यूं तो भारत के शहरों और गांवों के बीच एक पुल के तौर पर ही देखी जा रही हैं लेकिन अगर हम इसके फायदों पर विशेष रूप से गौर करें तो 'डिजिटल इंडिया' देश में इंटरनेट तक ही सिमटा हुआ नजर नहीं आएगा। ये एक ऐसे संसाधन के रूप में भी उभरकर सामने आता है जिसका प्रयोग पिछड़े और गुमनाम इलाकों को भी राष्ट्रीय फलक पर लाने के लिए किया जा सकता है।

लोक–पत्रकारिता के नये आयाम के लिए : इसके जरिए न सिर्फ इन इलाके के लोगों तक बेहतर सूचना प्रसारित की जा सकती है बल्कि स्थानीय लोगों को भी अपनी बातों को कहने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। डिजिटल इण्डिया को सिटिजन जर्नेलिज्म (लोक–पत्रकारिता) के लिए एक प्रेरणास्रोत के रूप में भी देखा जा सकता है।

शिक्षा के क्षेत्र में अभिनव प्रयोग : तकनीकी के माध्यम से शिक्षक ऑनलाइन अपने विचारों और संसाधनों को साझा कर रहे हैं जो विद्यार्थियों के लिए बहुमूल्य सामग्री सिद्ध हो रही है। शिक्षकों द्वारा ऑनलाइन साझा किए गए नोट्स हो, परिचर्चा हो, ब्लॉग अथवा ई–बुक हो, वीडियो या कोई अन्य सामग्री, सभी को डिजिटली संकलित कर उंगलियों पर उपलब्ध कराया जा सकता है। वृहद् पाठ्यसामग्री से बच्चों में शोध क्षमता का विकास होगा। कई तरह के गेम्स और एप्लीकेशंस के माध्यम से शिक्षण देने के प्रयोग में बच्चों की समझ और याददाश्त में भी वृद्धि पाई गई। एक लाख करोड़ रुपये के अति महत्वाकांक्षी डिजिटल इंडिया मिशन के अंतर्गत भारत के सभी स्कूलों को वाई–फाई से जोड़कर, वृहद् ज्ञान तंत्र खड़ा किया जाना है। इसके साथ ही स्तरीय पाठ्य सामग्री, ग्रामीण भारत के बच्चों के पास भी सहज उपलब्ध हो सकेगी। भारत की 2011 की जनगणना की रिपोर्ट में यह बात उभर कर सामने आई है कि छः से आठ वर्ष की उम्र के बीस प्रतिशत बच्चों को शब्द और संख्याओं का ज्ञान नहीं था। "गल्ली–गल्ली सिम–सिम" नामक एक अनूठी पहल के अंतर्गत बिहार और दिल्ली के कुछ स्कूलों में बच्चों को 'फन एंड लर्न' एप्लीकेशन के उपयोग से उत्साहजनक परिणाम मिले हैं।

स्वस्थ ग्रामीण भारत के लिए डिजिटल इंडिया : ग्रामीण महिलाओं का गिरता स्वास्थ्य, कुपोषण और सर्वाधिक मातृत्व मृत्युदर वर्तमान परिदृश्य में भारत की अनेक महत्वपूर्ण चुनौतियों में से एक है और इससे निपटने के लिए डिजिटलाइजेशन काफी हद तक सहायक हो सकता है। मसलन, एक परियोजना के तहत् सरकार ने 'आरोग्य सखी' नाम एक मोबाइल एप्लीकेशन लांच किया है जिसका इस्तेमाल गांवों की महिला उद्यमी सुरक्षापरक स्वास्थ्य जानकारी हर महिला तक पहुंचाने के लिए करेंगी। इन उद्यमियों को टैबलेट, स्मार्टफोन और डिजिटल स्वास्थ्य संबंधी यंत्र से लैस किया जाएगा ताकि वो हर परिवार के स्वास्थ्य की जानकारी स्वास्थ्य विभाग तक पहुंचाएं और डॉक्टर आसानी से दुर्गम प्रदेश के लोगों का भी समुचित इलाज कर पाएं। इसका मुख्य इस्तेमाल महिलाओं को उनकी गर्भावस्था और उसके पश्चात् समुचित स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए भी हो रहा है। ऐसे अनेक प्रयास भारत को स्वास्थ्य से संबंधित अपनी चिन्ताओं से निपटने में काफी मदद कर सकते हैं।

स्किल इंडिया और मेक इन इंडिया का सहयोगी : डिजिटल इंडिया न सिर्फ देश को डिजिटल बनाने वाला एक कदम है बल्कि ये सरकार की दो अन्य परियोजनाओं, देश को आत्मनिर्भर और तकनीकी रूप से कुशल बनाने को लक्षित महत्वाकांक्षी परियोजना 'स्किल इंडिया' और 'मेक इन इंडिया' का सहयोगी भी साबित हो सकता है। ये परियोजनाएं 'डिजिटल इंडिया' के साथ के जरिए बेहतर परिणाम दे सकती हैं।

लोगों की समस्याओं का समाधान और जागरुकता के प्रसार के लिए : इतना ही नहीं, डिजिटल इण्डिया का उपयोग आर्थिक और सामाजिक तौर पर पिछड़े दूरदराज के गांवों तक भी बिना रोकटोक पहुंचने के लिए किया जा सकता है। कुछ प्रदेशों में जहां अंधविश्वास का प्रभाव अधिक है और शिक्षा का कम, डिजिटलीकरण के जरिए लोगों तक आसानी से पहुंचा जा सकता है एवं उनकी समस्याओं के बारे में जाना जा सकता है, उसका हल ढूंढ़ा जा सकता है तथा उन्हें जागरूक बनाया जा सकता है।

महिला सशक्तीकरण के लिए : डिजिटल इंडिया को वर्तमान सरकार की महिला सशक्तीकरण की पहल के तौर पर भी देखा जा सकता है। चूंकि ये योजना लोगों को सशक्त बनाने की है। इसे आसानी से उन मुद्दों पर केन्द्रित किया जा सकता है जिससे गांवों, घर की महिलायें और बच्चियां अब तक जूझती आई हैं। उनकी प्रारम्भिक शिक्षा–दीक्षा से लेकर उनके खानपान तक के मुद्दे पर भी उन्हें जागरूक बनाया जा सकता है।

रोजगार के बढ़ते अवसर : डिजिटल इंडिया सरकार का एक ऐसा कदम है जिसका न सिर्फ सामाजिक पहलू है बल्कि व्यावसायिक पहलू भी है। इसके जरिए सरकार की मंशा गांव के उस युवा को भी राष्ट्रीय मानचित्र पर ले आना है जो अपने सामान को पड़ोस वाले शहर तक ले जाने में भी असमर्थ था।

भारत में कृषि क्षेत्र में वर्ष 2014 में सबसे ज्यादा 98 करोड़ ट्रांजेक्शन ई–सेवा क्षेत्र में हुआ। वर्तमान वर्ष में बेमौसम बरसात और ओला बारिश के कारण उत्पन्न हुई ग्रामीण किसानों की मुसीबतों के चलते ग्रामीण इलाकों में ई–ट्रांजेक्शन काफी बढ़ गया, तब यह अहसास हुआ कि किसानों का दुख दूर करने में ई–टेक्नोलॉजी काफी मददगार है। सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशंस ऑफ इंडिया (सी.ओ.ए.आई.) के अनुसार भारत में कुल 68.7 करोड़ जी.एस.एम. मोबाइल की संख्या में से 33 करोड़ मोबाइल ग्रामीण भारत में हैं। इस तरह किसानों का ई–ट्रांजेक्शन सरकार के साथ काफी बढ़ने की उम्मीद है। उपरोक्त विश्लेषण देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय किसान मोबाइल टेक्नोलॉजी के जरिए अपने समाधानों को पाने के लिए उत्साहित और प्रयत्नशील हैं।

मौजूदगी, विशेषकर मोबाइल पर उसका सरकार से सीधा सम्पर्क है।

3.5 बिलियन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन–ई–व्यवहार, वर्ष 2014 में किए गए उसमें से आधे ग्रामीण इलाकों से आए जबकि इसके पिछले वर्ष केवल 20 प्रतिशत ही ई–व्यवहार पारस्परिक रूप से, किसान और सरकार के बीच सम्पादित हुए। ये आंकड़े इंडियास्पेंड ने भारत सरकार द्वारा बनाए गए गवर्नेंस डैशबोर्ड से प्राप्त किए हैं। ई–सेवाओं के इस्तेमाल का यह मतलब नहीं है कि उनकी वर्तमान गुणवत्ता वही है जोकि वास्तव में होनी चाहिए, लेकिन कम्प्यूटर और मोबाइल सहायक आधारित आंकड़े भारतीय किसानों और सरकारों के बीच हुए संदेशों के आदान–प्रदान के अभिनव रिकार्ड्स हैं। मोबाइल बैंकिंग ग्राहकों को सुग्राह्यता और सुविधा प्रदान करती है और इस मोबाइल बैंकिंग से हम निरन्तर सेवा प्राप्त कर सकते हैं। अतः प्रौद्योगिकी आजकल बैंकिंग का अविभाज्य अंग बन गई है और इसने बैंकिंग उत्पादों और ग्राहकों को दी जाने वाली सेवाओं के वितरण में पूर्णतः क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं, प्रौद्योगिकी वर्ग विशेष कर बैंकिंग से विशाल बैंकिंग की ओर अग्रसर हो रहा है।

भारत के सम्पूर्ण ई–ट्रांजेक्शन का 30 प्रतिशत जोकि 98 करोड़ है, केवल कृषि क्षेत्र में दर्ज किये गये। उपरोक्त सभी ई–ट्रांजेक्शन ऐसे हैं जिनके माध्यम से किसानों ने निम्न क्षेत्रों में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की है, ये हैं–मौसम, मृदापरीक्षण, नए रजिस्ट्रेशन, नित्य के बाजार भाव और जिंस की बाजार में आवक जिससे भारत भर में फैली 3,200 कृषि मंडियों के बारे में रजिस्टर्ड उपभोक्ताओं को एस.एम.एस. और ई–मेल के जरिए महत्वपूर्ण जानकारी हासिल हो जाती है। विभिन्न कृषि सलाहकार केन्द्रों में भारतीय किसानों द्वारा पंजीयन कराने वालों की संख्या में 3 गुना वृद्धि हुई है जोकि वर्ष 2013 में 37 लाख से बढ़कर 2014 में 93 लाख हो गई। यद्यपि यह सच है कि काफी संख्या में किसान मोबाइल का इस्तेमाल परामर्श मांगने के लिये करते हैं।

गांव में ई–गवर्नेंस उपयोग में रिकॉर्ड 35 प्रतिशत की वृद्धि : ई–गवर्नेंस का यह मतलब नहीं है कि इंटरनेट पर एक वेबसाईट खोल दी और प्रार्थना–पत्रों के निवारण के कार्य होने लगे, बल्कि सरकार को ई–गवर्नेंस के लिये समुचित समाधान और कुशल और सक्षम अधिकारी नियुक्त करने होंगे, जो शिकायती–पत्रों पर उचित और शीघ्र कार्य कर सकें।

ई–गवर्नेंस के क्षेत्र में तीसरा सबसे बड़ा कार्यक्षेत्र : सरकारी बिलों और अन्य सुविधाओं का इंटरनेट वेबसाईट के माध्यम से भुगतान होता है। इस बिल भुगतान क्षेत्र में भी गुजरात का स्थान प्रथम है, जहां 6 करोड़ ई–ट्रांजेक्शन हुए हैं। इसके बाद कर्नाटक और आंध्रप्रदेश आते हैं।

ई–सेवाओं के विस्तार के कारण बिचौलियों/दलालों का खात्मा हो जाता है और सरकारी सुविधाएं जल्दी निष्पादित हो जाती हैं। भारत की विशालता और हर तरफ की विभिन्नताओं के चलते मूलभूत सुविधाओं को भारत के सुदूरतम इलाकों तक पहुंचाने में केवल एक पारदर्शी ई–गवर्नेंस ही सहायक हो सकता है। हाल में भारत में सम्पादित 35 लाख ई–ट्रांजेक्शन इस बात का प्रमाण हैं कि सामान्य भारतीय नागरिक अपने मूलभूत कार्यों को पूरा करने के लिए लम्बी और बोझिल कतारों में घंटों खड़ा होने के बजाए, वह आज का एक अच्छा औजार मोबाइल सेट का इस्तेमाल करना पसंद करेगा।

बढ़ती आबादी का दबाव और पर्यावरण की चुनौतियों के बीच भारत में खेती और तकनीक के सदुपयोग पर गहन शोध की आवश्यकता है। विगत् कुछ योजनाओं ने निश्चित तौर पर किसानों को कुछ राहत पहुंचाई है। इसमें ग्रामीण जीवनशैली के सभी क्षेत्रों, विशेष रूप से सामाजिक रहन–सहन, स्थानीय व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग, ई–गवर्नेंस आदि में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। इसके अलावा रोजमर्रा की जरूरतों जैसे जमीनों के नक्शे और उसके स्वामित्व या टैक्स संबंधी सूचना, रेलवे टिकट बुकिंग, अस्पतालों की ओ.पी.डी. सुविधाओं तक पहुंच जैसी कई सुविधाएं, सरल और सहज रूप में उपलब्ध होने लगी हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में गांव में ही दैनिक जीवन की जरूरत वाली सारी वस्तुएं उपलब्ध हो जाती हैं। आज गांवों में हर क्षेत्र में हो रहे परिवर्तनों की झलक साफ देखी जा सकती है।

(अतिथि विद्वान, अर्थशास्त्र विभाग,
शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बीना, जिला सागर, म.प्र.)
ई–मेलः neeraj_gautam76@yahoo.co.in